

## विचार बिन्दु

“जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।”

- अरविन्द कटोक

## मितव्ययता की नीति अब सरकारों की प्राथमिकता की सूची में नहीं

हमें याद नहीं पड़ता सरकार ने अपने खर्चों में मितव्ययता की बात पिछली बार कब कही। अब तो राज में बैठे नेता राजकोष को हाथ खोल कर लूटने में ही अगले चुनावों में अपने और अपने दल की विजय देखते हैं। आजादी के बाद संविधान से मिली लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जब सरकारें वास्तव में लोक कल्याणकारी होती थीं तब वह मितव्ययता की बातें करती थीं। अब नहीं करती। राजकोष का पैसा लोगों के हाथ में जाये, उनको अधिक उत्पादक बनाये इससे किसी को क्या विरोध हो सकता है, किन्तु राजकोष का पैसा ऐसे कामों पर खर्च हो जाये, जो दिखावे की भव्यता पर खर्च हो यह तो कोई नहीं चाहेगा। मितव्ययता का आशय यह होता था कि सरकार अपने तंत्र पर खर्च कम करके पैसे बचाये और उसे आमजन के कल्याण पर खर्च करे। इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पदों को बढ़ाना बंद कर दे और नियमित पदों को निजी ठेकों पर देने लगे और लोक कल्याण के कामों से अपनी सीधी हिस्सेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। दुर्भाग्य से जन कल्याण के दो बड़े क्षेत्र- शिक्षा और स्वास्थ्य- इन दोनों कामों से अब निर्वाचित सरकारें अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में नजर आती हैं। वैचारिकता से कटे और जमीनी हकूकों से ज्ञान कर अनजान रहने वाले नये जमाने के राजनेता अब जनसेवा का मुखौटा पहन कर सब कुछ अपने लिये और अपनों के लिये चाहने लगे हैं। आज की हकूकीकत यह है कि जन प्रतिनिधियों के वेतन भत्तों, रहन सहन, उनके सरकारी आवासों की साज सज्जा तथा उनके निजी खर्चों की मद में अश्लीलता की हद तक पैसा खर्च किया जाने लगा है। सबसे देखा है कि पिछली अशोक गहलोट के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी धन की फिजूलखर्ची की सीमाएँ किस प्रकार लांघी थी। हालाँकि गहलोट अपना राज बचाने में असफल रहे, किन्तु उन्होंने लोकतान्त्रिक श्रुतिका के बांध में जो सुराज कर दिया वह, यदि बढ़ता रहता हो तो, एक दिन वह उसे दहा भी सकता है। मगर राजनेताओं, खासकर निर्वाचित प्रतिनिधियों में, इसकी कोई फिक्र नजर नहीं आती है। इसका एक बड़ा उदाहरण जयपुर में उनके लिये बनाये गए आलीशान आवास हैं। पिछली सरकार ने उनके लिये जयपुर में राज्य विधान सभा के पास करीब पांच सौ करोड़ रुपयों से ऐसे विलासिता वाले आलीशान आवास बनाये हैं जिनकी कल्पना भी उनके बहुसंख्यक मतदाता नहीं कर सकते। विधायकों को मिलने वाले इन सभी फ्लैटों में प्रत्येक में चार सोने के कमरे, एक बड़ा हॉल, खुला हवादार भव्य रसोईघर और आधुनिक सुविधाओं वाले स्नानघर व शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही हर फ्लैट में एसी, आरामदेह बड़े पलंग, फ्रिज, सोफा सेट समेत कई तरह की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। क्योंकि आलीशान और भव्य स्थान पर रहने वालों को अति आधुनिक सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए इसलिए पूरे परिसर के कॉमन एरिया में 80 से अधिक अत्याधुनिक एवं हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिसर में डबल बेसमेंट में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें एक साथ 921 चार पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। कैसी विडंबना है कि सरकार जब नये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय या अस्पताल और डिस्पेंसरीयाँ खोलती है तो उनके लिये भवन बनाने के लिये उसके पास पैसे नहीं होते, मगर जन प्रतिनिधियों को आरामदायक रहन सहन देने के लिये पैसे का दरिया बहा दिया जाता है। लंगोटी वाले फकीर महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का ढोंग रचने वाले गहलोट को गांधी वाटिका (म्यूजियम) पर राजकोष का 85 करोड़ रुपये खर्च करते हुए कोई ग्लानि नहीं हुई। अब देखें तो राजनीति के समूचे परिदृश्य में सभी पार्टियाँ एक जैसी हो चली हैं। सभी विलासिता पर अधिक खर्च करने को तत्पर नजर आती हैं।

जिस प्रकार की फिजूलखर्ची विधायकों के भव्य आवासों पर हुई है वैसी ही फिजूलखर्ची नये बनने वाले सरकारी ऑफिसों के भवनों के निर्माण पर भी खुल कर हो रही है। जनता की गाढ़ी कमाई के राजकोष से बनने वाले ये सरकारी भवन पांच सितारा होटलों के भवनों से प्रतिस्पर्धा करते लगते हैं। सरकारी ऑफिस में काम करने के लिये छोटे और बड़े बाबू रोज दिन में दस से पांच बजे के बीच हफ्ते में पांच दिन बैठते हैं। अन्य सरकारी छुट्टियाँ अलग होती हैं। इतने थोड़े समय कर्मचारियों को बिटाने के लिये आलीशान व्यवस्था क्यों होनी चाहिए जब कि जिनके वे सेवक हैं उनमें से 80 प्रतिशत गरीबी और अभावों में जीते हैं। बहुतेरों को याद होगा कि 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सलाह दी थी कि सरकारी ऑफिसों के भवन, जिन में दिन में कुछ घंटे बैठ कर कर्मचारी काम करते हैं, वे शानदार बाजु और साज सज्जा वाले होने की बजाय साधारण कामकाजी व्यवस्था वाले होने चाहिए। उन पर बड़े खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान जब जयपुर में शासन सचिवालय के पीछे चिकित्सा विभाग का भवन बना तो उसे तत्कालीन मुख्य मंत्री हरदेव जोशी ने उसे वैसा ही बनाने के निर्देश दिए जैसी तत्कालीन प्रधानमंत्री की थी। और वह वैसा ही बना। मगर वह सोच तो कब की हवा में उड़ गई और हम आज सरकारी कार्यालयों के आलीशान और भव्य भवनों को निजी कॉर्पोरेट संस्थानों के भवनों से प्रतिस्पर्धा करते पाते हैं।

यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी चुनावी व्यवस्था में जो लोग जनता के प्रतिनिधि बन कर विधायिका में जाते हैं उनका आमजन से नाता सिर्फ दिखावटी होता है। भले ही हमारा संविधान सार्वभौम सत्ता हम भारत के लोगों के हाथ में बताता है, मगर मतदान की मशीन का बटन दबाने के साथ ही यह सत्ता निर्वाचित राजनेता को हस्तांतरित हो जाती है। चुनावों में कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला स्थानीय लोग अपने में से नहीं करते बल्कि यह काम राजनैतिक पार्टियों की आलाकमान अपने नजदीकी लोगों की राय से करती है। दूसरी तरफ राजनैतिक पार्टियों में खुद में कोई लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार सामंती जमाने में रियासती ढांचे में खींचतान और कुचक्र चरते रहते थे वे सब अब नये रूपों में आज भी मौजूद है। पिछले दो दशकों में लोकतांत्रिक प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण बदलावआया है वह है राजनीतिक उद्यमियों का उदय। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक प्रणालीका अपने हित में उपयोग करते हैं। मतदाताओं को उन्हीं राजनीतिक उद्यमियों में से ही लोकसभा और विधानसभाओं के लिये अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं। पश्चिम में हुआ एक अध्ययन बताता है कि ऐसे उद्यमी राजनेता लोकतांत्रिक संस्थाओं के आधारभूत मानदंडों को तोड़ते हैं। उनकी शैली सही लगने वाली बातों के प्रति भावनात्मक अपील तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध नकारात्मक भावनाएँ भड़काने के लक्ष्य से प्रेरित होती हैं।

मतदाताओं की प्राथमिकताओं और व्यवहार में भी अब नाटकीय परिवर्तन हुए नजर आने लगे हैं। वे दिन लद गए जब मतदाता जीवन भर एक ही पार्टी का समर्थन करता था। आज का मतदाता बाजारी उत्पाद के उपभोक्ताओं की तरह व्यवहार करता है, जो अक्सर प्रचार की हवा में बह कर अपना चयन बदलता रहता है। ऐसा लगता है मानो मतदाता शेर बाजार के व्यक्तिगत निवेशक की भाँति व्यवहार कर रहा है। लोकतान्त्रिक मतदान संसेक्स की भाँति हो गये हैं। अचानक किसी शेर (पार्टी) के भाव बड़ जाते हैं और बहुसंख्यक निवेशक कुछ पाने की चाह में उसी पर दांव लगा बैठते हैं। कभी वह शेर घडाम से नीचे भी आ गिरता है। लोकतान्त्रिक चुनाव में अब वैचारिक पक्ष गौण हो गया है। अमरीकी विश्वविद्यालयों की दो प्रोफेसरों ने मिल कर एक किताब लिखी है पोलिटिकल आंत्रेप्रेन्योरस जिसमें वे कहती हैं कि राजनीतिक उद्यमी नेताओं के आगमन से चुनावी प्रचार में उम्मीदवारों की बयानबाजी की शैली का महत्व बढ गया है।यह शैली है प्रतिस्पर्धी पर शब्दों का कठोर प्रहार। इसमें नये मोशल मीडिया का भरपूर उपयोग होता है। जो वक्तव्य मुख्यधारा के मीडिया में नहीं दिया जा सके वह सोशल मीडिया के जरिये इतना फैला दिया जाता है कि वह उफन कर मुख्य धारा के मीडिया में भी उजगह पाने लगता है। सरकार अपने प्रचार परपैसे उड़ाती है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रचार से यह जताने की कोशिश होती है कि सरकार की ऐसी छवि बनाई जाय जिस पर आम जनता मोहित होऔर अगले चुनावों में उसकी पार्टी को उसका वोटों से मालामाल कर दे। इस मामले में नई भाजपा सरकार भी पिछली गहलोट सरकार से अलग नजर नहीं आ रही है। सरकार बदलने पर राजधानी के चौराहों पर लगे प्रचार के बड़े-बड़े होर्डिंग पर बस नेताओं की तस्वीरें भर बदल गई हैं। प्रचार से अपनी नैया खेने के लिये वर्तमान सरकार ने एक टैंडर निकाला है जिसमें यूट्यूब पर 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल चलाने के लिये दस करोड़ रुपयों का खर्च करने जा रही है, भले ही सरकार का पत्र प्रचार का अपना महकमा काम कर रहा है। मगर इस पर चर्चा कौन करे? भव्य भवन वाली विधान सभा में बैठ कर विधायिका के लोग साल में सौ दिन भी अपना दायित्व नहीं निभाते हैं। उनकी चर्चाएँ भी राज्य के लोगों का जीवन कम कष्टप्रद करने के लिये नहीं बल्कि दलीय आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखने के लिये अधिक होती हैं। सभी जल्दी अमीर होना चाहते हैं और उद्यमी लोगों ने राजनीति को भी अमीरी की तरफ ले जाने का रास्ता बना लिया है। शायद इसीलिए राजकोष के पैसे को सही तरीके से और समझदारी से खर्च करने की दिलचस्पी सत्ता में बैठे लोगों में नजर नहीं आती।

अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा  
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

## साइबर अटैक का बढ़ता खतरा और भारतीय जनमानस



अविनाश जोशी

आज इंटर्नेट हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंगों में से एक बन गया है। वह हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। साइबरस्पेस हमें वस्तुतः दुनिया भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है। हमारी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले एवम दस्तावेज कंप्यूटर में संताहित रहते हैं। हमारा पूरा वित्त संबंधित लेखा जोखा भी ऑनलाइन ही संताहित है।

साइबर स्पेस हमारे जीवन की आधार रेखा है इसलिए साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हथेलों से बचाने का माध्यम है।

इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह शब्द व्यवसाय से लेकर मोबाइल कंप्यूटिंग तक विभिन्न संदर्भों में लागू होता है। नेटवर्क सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क को चुसपैठियों सा सुरक्षित करने का तरीका है, चाहे लक्षित हमलावर हों या अवसरवादी मैलवेयर। आज विश्व में साइबर खतरा तत्रिंत्र गति से विकसित हो रहा है, हर साल डेटा उल्लंघनों की संख्या बढ़ रही है। रिस्कनेस सिस्कोरिटी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अकेले 2019 के पहले ही महीनों में डेटा उल्लंघनों से चौकाने

वाले 7.9 बिलियन रिकॉर्ड उजागर हुए थे। यह आंकड़ा 2018 की समान अवधि में उजागर हुए रिकॉर्ड की संख्या से दोगुने (112) से भी अधिक थे।

चिकित्सा सेवाओं, खुदरा विक्रेताओं और सार्वजनिक संस्थाओं ने सबसे अधिक उल्लंघनों का अनुभव किया, अधिकांश घटनाओं के लिए दुर्भावनापूर्ण अपराधी जिम्मेदार थे। इनमें से कुछ क्षेत्र साइबर अपराधियों के लिए अधिक आकर्षक हैं क्योंकि वे वित्तीय और चिकित्सा डेटा एकत्र करते हैं, लेकिन नेटवर्क का उपयोग करने वाले सभी व्यवसायों को ठाहक डेटा, कॉर्पोरेट जासूसी या ठाहक हथेलों के लिए लक्षित किया जा सकता है।

साइबर खतरे का स्तर लगातार बढ़ने के साथ, साइबर सुरक्षा समाधानों पर वैश्विक खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि साइबर सुरक्षा का खर्च 2026 तक वैश्विक स्तर पर 260 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। दुनिया भर की सरकारों ने संगठनों को प्रभावी साइबर-सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन के साथ बढ़ते साइबर खतरे के प्रति जागरूकता पै ध्यान दिया है। अमेरिका में नेशनल इंटीट्रैक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने एक साइबर-सुरक्षा ढांचा बनाया है। दुर्भावनापूर्ण कोड के प्रसार से निपटने और शीघ्र पता लगाने में सहायता के लिए, रूपरेखा सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की निरंतर, वास्तविक समय की निगरानी की सिफारिश करती है। यूके सरकार के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन, "साइबर सुरक्षा के लिए 10 कदम" में सिस्टम निगरानी के महत्व को प्रतिध्वनित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा केंद्र नियमित रूप से इस बारे में मार्गदर्शन प्रकाशित करता है कि संगठन नवीनतम साइबर-सुरक्षा खतरों

का मुकाबला कैसे कर सकते हैं।

साइबर आक्रमण या साइबर हमला एक प्रकार का अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इसे अंडोजी भाषा में साइबर अटैक कहते हैं। सामान्यतः साइबर आक्रमण का संचालन अनामक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण डाटा की चोरी करने के लिये किया जाता है।साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा की चोरी, क्षति, अनधिकृत पहुँच या किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बचाने की प्रथा है।

साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार, सैन्य, कॉर्पोरेट, वित्तीय और चिकित्सा संगठन कंप्यूटर और अन्य उपकरणों पर अभूतपूर्व मात्रा में डेटा एकत्र, संसाधित और संताहीत करते हैं। उस डेटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संवेदनशील जानकारी हो सकता है, चाहे वह बौद्धिक संपदा, वित्तीय डेटा, व्यक्तिगत जानकारी, या अन्य प्रकार का डेटा हो, जिसके लिए अनधिकृत पहुँच या प्रदर्शन के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। संगठन व्यवसाय करने के दौरान नेटवर्क और अन्य उपकरणों पर संवेदनशील डेटा प्रसारित करते हैं, और साइबर सुरक्षा उस जानकारी और इसे संसाधित करने या संताहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों की सुरक्षा के लिए समर्पित अनुशासन का वर्णन करती है। जैक-जैस साइबर हथेलों की मात्रा और परिष्कार बढ़ता है, कंपनियाँ और संगठन, विशेष रूप से जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य या वित्तीय रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है, उन्हें अपने संवेदनशील व्यवसाय और कर्मियों की जानकारी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है। कुछ वर्षों पहले देश के शीर्ष स्तुफिका अधिकारियों ने अगाह किया था कि साइबर हमले और डिजिटल जासूसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यहाँ तक कि

आतंकवाद भी।

जागरूकता एवम शिक्षा साइबर-अपराधों की रोकथाम के बारे में सूचना के प्रसार के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और युवा आबादी साइबरस्पेस में अपनी भागीदारी के बारे में जागरूक होने तथा साइबर सुरक्षा के लिये और साइबर अपराध रोकने के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिये बल गुणक के रूप में कार्य कर सकती है।साइबर सुरक्षा जागरूकता का मतलब यह है कि साइबर सुरक्षा के बारे में उपयोगकर्ताओं को कितना पता है कि उनके नेटवर्क को खतरा है और वे जो जोखिम पेश करते हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक नेटवर्क के भीतर सबसे कमजोर लिंक और प्राथमिक भेद्यता माना जाता है। संगठन अपने नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाने और कमजोरियों को खत्म करने के लिए धन आवंटित करते हैं। अंत उपयोगकर्ता होने के नाते एक बड़ी भेद्यता है, सुरक्षा में सुधार करने के लिए तकनीकी साधन पर्याप्त नहीं हैं: संगठनों को साइबर सुरक्षा की व्यक्तिगत जागरूकता के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए। उन्हें वर्तमान खतरों पर कर्मचारियों को शिक्षित करना चाहिए और उनसे कैसे बचना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का औपचारिक समूह 'क्वाड' साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'प्रभावी लॉगिंग' और संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर सहमत हो गए हैं। एवम अपने वाले समय में साइबर सुरक्षा पे मिल के कार्य करेंगे। साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं।

ए आई चेट बोट की मदद से अब पुलिस केस निपटायागी और लगातार इसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप भी इसका आसानी से लाभ उठा सकते हैं। साइबर फ्रॉड के मामलों से बचने के लिए सरकार और सरकारी तंत्र अलग-अलग तरीके अपना रहा है।

यूजर्स को भी समय समय पर इससे होने वाले खतरों से अवगत कराया जाता है। साथ ही इससे बचने के तरीके भी बताए जाते हैं।

भारत में 2023 में लगभग 85 लाख उपकरणों पर 40 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए हैं। यानी हर मिनट 761 साइबर हमले हुए। इनमें से सूरत में 15 फीसदी और बंगलूरु में 14 फीसदी सबसे अधिक मामले देखे गए हैं। इनमें से 50 फीसदी से अधिक मीडिया और नेटवर्क ड्राइव से जुड़े हैं। सुरक्षा उपायों में असमानता से वैश्विक स्तर पर साइबर खतरे बढ़ रहे हैं। यह दावा विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2024 जारी रिपोर्ट में किया है।एकसेंचर के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में गलत जानकारी फैलाने या सार्वजनिक धारणा में हरेफेर करने के लिए एआई जनित डीपफेक से उत्पन्न खतरों को उद्धृत किया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में दुनिया के 10 में 8 करोड़ बार साइबर सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यह रिपोर्ट तब सामने आई है, जब दुनिया के 45 से ज्यादा देशों में चुनाव होने वाले हैं।

साइबर क्राइम से जुड़े ज्यादातर मामले एक्ट 2008 के तहत दर्ज किए जाते हैं। इसमें अपराधी के द्वारा किए गए क्राइम की श्रेणी तय की जाती है और उसके अनुसार आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ धारा 43, 65, 66 और 67 के तहत केस चलते हैं।

भारत को व्यापक और अद्यतन कानून बनाने की आवश्यकता है जो साइबर सुरक्षा के सभी पहलुओं, जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, साइबर जासूसी और साइबर धोखाधड़ी को दायरे में ले।

अविनाश जोशी,  
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

## 140 रुपए का प्लग खराब निकला, कंपनी को देने होंगे 9500

बीकानेर, बिजली उपकरणों से जुड़ी एक कंपनी का पावर प्लग खराब होने पर उपभोक्ता आयोग ने 9500 रुपए का जुर्माना लगाया है। पावर प्लग की कीमत 140 रुपए है। बीकानेर से जुड़े इस मामले में पिछले दिनों उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। नोखा रोज पर रहने वाले एडवोकेट अनिल सोनी ने इस संबंध में एक परिवार उपभोक्ता आयोग के समक्ष ल गया था। सोनी ने बताया कि उसने कोटेट पर स्थित महेश इल इंट्रक कंपनी से एक पावर प्लग की खरीद की थी। इसमें 140 रुपए का पावर प्लग था और 30 रुपए का वायर खरीदा था। महेश इल इंट्रक कंपनी से इस सामान का बकायाद बिल ल या

गया। खरीद के दो महीने बाद पावर प्लग खराब हो गया।

एकर कंपनी का ये पावर प्लग काम नहीं कर रहा था तो दुकानदार को इसकी शिकायत की गई। जिसका समाधान न तो दुकानदार ने किया और न एकर कंपनी ने। इस पर उपभोक्ता ने अधिकारों का उपयोग करते हुए एकर कंपनी के मात्र 120 रुपए के पावर पूरा में खराबी पर परिवार देते हुए पूरा की राशि देने के साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माना ल गाने की मांग रखी। इसमें दस हजार रुपए मानसिक संतोष के और दस हजार रुपए परिवार व्यय के देने की डिमांड रखी। ग्राहक कंपनी की तरफ से आयोग के समक्ष शपथ पत्र भी दिया गया। ये शपथ पत्र एकर कंपनी के अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर सुरेंद्र नाथ ने दिया। जिसमें अपनी कंपनी की तारीफ करते हुए इस मामले को खारिज करने का आग्रह किया गया।

इस अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि चूंकि पावर प्लग और वायर की कीमत महज 170 रुपए है। ऐसे में मानसिक संतोष के रूप में दस हजार रुपए का दावा सही नहीं है। मानसिक संतोष के रूप में 6 आई हजार रुपए देने का निर्णय दिया गया है। वहीं परिवार व्यय के रूप में दस हजार की डिमांड थी, आयोग ने पांच हजार परिवार व्यय देने के आदेश एकर कंपनी को दिए हैं। दो हजार रुपए का हर्जाना परिवारी एडवोकेट अनिल पहले ही बसल चुके हैं।

## डेंगू संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी

30 सैपल की जांच हुई, 24 पॉजिटिव आए, इसमें चार दूसरे जिलों के मरीज रिपोर्ट

बीकानेर, डेंगू संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। डेंगू की रिपोर्ट में 24 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसमें चार पेशेंट दूसरे जिलों के थे। करीब 300 पेशेंट्स की डेंगू जांच करवाई गई थी। इसमें 20 मरीज बीकानेर के तथा 4 मरीज दूसरे जिलों के डेंगू पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू मरीजों की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ कर अब 8 प्रतिशत हो गई है।

सीएमएचओ राजेश गुप्ता ने बताया कि जिन मरीजों की रिपोर्ट

है, वहां भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिक संबंधित मरीजों का फॉबैडक ले रहे हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों को तल-1-मुना और मसाला दार भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे पेट में जल न और गैस जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। कैफोन युक्त पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। इसके बजाय प्राकृतिक और ताजे तरल पदार्थों का सेवन करें। मसाला दार भोजन से एसिडिटी बढ़ने की संभावना रहती है जो मरीजों की स्थिति

को और बिगाड़ सकती है। खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे सिरका और अचार से परहेज करना चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया होने की संभावना होती है जो संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकते हैं। डेंगू के मरीजों को अच्छी तरह से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। शुगर युक्त भोजन और अत्यधिक तेल से भरपूर सैंड्स से बचें। यह शरीर के लिए भारी होते हैं और योग प्रतिक्रम क्षमता पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

इनका कहना है - डेंगू वायरस से संक्रमित होना शरीर के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, खासकर क्योंकि इससे पेटल टस (रक्त के थक्के बनाने वाले) कोशिकाएं) का स्तर गिरता है और पॉजिटिव मरीजों के लिए उचित खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही पोषक तत्व बीमारी से उबरने में मदद करता है। डॉ. विकास पारीक

सौनियर फिजिशियन, बीकानेर।

## राशिफल बुधवार 13 नवम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

संचार करेगा।

रविवयोग रात्रि 3.11 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, मन्वादि कालिदास जयंती, तुलसी विवाह है। पंचक रात्रि 3.11 पर समाप्त होगा।

श्रेष्ठ चौघडिया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9.30 तक, शुभ 10.50 से 12.11 तक, चट 2.52 से 4.12 तक, लाभ-अमृत 4.12 से सूर्यास्त तक

राहुकाल: 12.00 से 1.30 तक, सूर्योदय 6.43 सूर्यास्त 5.33

**मेष**  
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड़ बनी रहेगी। आज समय अर्नगल कार्यों में खराब हो सकता है।

**वृष**  
आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

**मिथुन**  
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अडचनें दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बरने लगेगे। नवीन कार्य योजना का क्रियाव्यवण होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**सिंह**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

**कन्या**  
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**तुला**  
व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बरने लगेगे। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृश्चिक**  
परिवार में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भाग-दौड़ रहेगी।

**धनु**  
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। अतिथियों का आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**मकर**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**कुंभ**  
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बरने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

**मीन**  
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्ययोजनानुसार बरने लगेगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।